

1. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा ईरान समर्थित गुटों की आतंकी गतिविधियाँ समाप्त हुए बिना पश्चिम एशिया में शांति संभव नहीं है।
2. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर डिजिटल और नागरिक हितैषी पहलों की उपलब्धियाँ बताईं।
3. खेत बचाओं अभियान के तहत रंगत क्षेत्रों के किसानों को सतत् कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया गया।
4. दक्षिण अंडमान में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मादक पदार्थों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई।

अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबू धाबी में संवाददताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष-विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने इन ख़बरों को खारिज़ किया कि अमरीका ईरान के लिए तीन सौ अरब डॉलर के प्रस्तावित पुनर्निर्माण कोष के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों से धन जुटाएगा।

ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद, भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर-ज़रूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नज़र रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने को कहा गया है।

आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून, उन्नीस सौ सड़सठ को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप-आधारित ई-पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ, इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं।

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के सतत् अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा आज शहीद द्वीप के नीलकेंद्र गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सरकारी राजस्व भूमि पर किए गए अवैध कब्जे और अनाधिकृत वृक्षारोपण को चिह्नित कर हटाया गया। इस अभियान में लगभग 1000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर पुनः सरकारी खाता में दर्ज कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि का अनाधिकृत उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने दोहराया कि अतिक्रमण के मामलों में "शून्य सहिष्णुता" की नीति अपनाई जा रही है और दोषियों के विरुद्ध संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अतिक्रमण की सूचना देने की भी अपील की है।

आईसीएआर-के वी के, निम्बूडेरा द्वारा "खेत बचाओ अभियान" के अंतर्गत सतत् कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 22 से 23 जून तक रंगत ब्लॉक के निम्बूतला और धर्मापुर गांवों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम यूटी एटी एमए और कृषि विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि तकनीकों के बारे में जागरुक करना था। इस दौरान किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व, वर्मीकम्पोस्ट एवं कम्पोस्ट के माध्यम से समन्वित पोषक प्रबंधन, जैव उर्वरकों से बीज उपचार, वैज्ञानिक धान उत्पादन तकनीक, समेकित कीट प्रबंधन तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने जलवायु अनुकूल खेती तथा इनपुट के प्रभावी उपयोग पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें कुल छियासी किसानों ने भाग लिया।

नशा मुक्ति जागरूकता सप्ताह के तहत दक्षिण अंडमान जिले में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इसी क्रम में कल दक्षिण अंडमान जिला नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक जिला मजिस्ट्रेट पल्लवी सरकार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले में बढ़ती नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, सतत् प्रयास तथा बहु-हितधारक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित विभागों को आपसी सहयोग बढ़ाने, सूचना एवं खुफिया जानकारी को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। आम जनता से भी मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी सूचना MANAS हेल्पलाइन 1933 पर देने की अपील की गई।

मत्स्य पालन विभाग केंद्रशासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम 'मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति – आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं' लागू कर रहा है। गैर-जनजातीय श्रेणी के लिए पचास प्रतिशत और जनजातीय श्रेणी के लिए पचहत्तर प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीपसमूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर-मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार दो वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026-27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगरपालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म और विस्तृत नियम व शर्तें मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों और नजदीकी मत्स्य उप-केंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उप-केंद्र में जमा किए जा सकते हैं।

ग्रामीण संपर्क व्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में ग्राम पंचायत मन्नारघाट में दो महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष पी. उम्मर ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में फरारगंज प्रखंड की खंड विकास अधिकारी ललिता तिग्गा, ग्राम पंचायत मन्नारघाट के उप-प्रधान ए.पी. नौफल, पंचायत प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। पहले कार्यक्रम के तहत मलापुरम में मुख्य सड़क से हनीफा हाउस तक नव-निर्मित ग्रामीण सड़क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि नई सड़क के

निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी तथा यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।